P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-2* October- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

निर्वाचित महिलाओं में राजनीतिक संचेतना : एक अध्ययन (बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विशेष सन्दर्भ में)

Political Consciousness in Elected Women: A Study (With special reference to the Bundelkhand region)

Paper Submission: 15/10/2020, Date of Acceptance: 26/10/2020, Date of Publication: 27/10/2020

शक्ति गुप्ता
सहायक प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय. हमीरपुर भारत

स्वामी प्रसाद
समाजशास्त्र विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय. हमीरपुर (उ0प्र0)
भारत

सारांश

भारत ग्राम प्रधान देश है। जब तक ग्रामवासियों का प्रतिनिधित्व शासन और सत्ता में नही होगा तब तक ग्राम विकास की कल्पना करना निर्थक होगा साथ ही लोकतन्त्र की सफलता हासिल करना संभव नही होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायतीराज व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से ग्रामीण विकास संभव हो सकता है। साथ ही कोई भी सरकार जन सामन्य के सम्पर्क में आकर उनके कल्याण के लिए कदम उठा सकती है।

राजनीतिक संचेतना से आशय राजनीतिक परिदृश्य के सम्बन्ध में जानकारी से है। राजनीतिक संचेतना का सहभागी अभिविन्यास एवं राजनीतिक दक्षता से गहरा सम्बन्ध होता है। इस प्रकार राजनीतिक संचेतना को राजनीतिक सामाजीकरण की संज्ञा दी जाती है। सामाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति ज्ञान, निपुणता, विश्वासों, मूल्यों, मनोवृत्तियों को प्राप्त करता है तथा यह उसे समाज के एक प्रभावशाली सदस्य के रूप में कार्य करने के योग्य बनाती है।

राजनीतिक सामाजीकरण वास्तव में राजनीति एवं राजनीतिक व्यवहार के क्षेत्र में सामाजीकरण की प्रक्रिया का परिसीमन है। यह सीख की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था के आदेशों एवं मूल्यों का अन्तरीकरण करता है।

डासन तथा प्रिविट ने इसे वह प्रक्रिया माना है जिसके द्वारा नागरिक राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व होता है। राजनीति संचेतना का स्तर लोकतंन्त्र को सफल संचालन में दूरगामी परिणामों का द्योतक है। यदि प्रतिनिधियों की राजनीतिक प्रक्रियाओं की जानकारी ठीक होगी तो राजनीतिक मुददों एवं शासकीय कार्यो में उनकी भागीदारी अर्थपूर्ण होगी। इससे राजनीतिक निर्णय लेना सरल होगा ।

India is a village dominated country. Unless the representation of the villagers is in governance and power, it would be meaningless to imagine village development, as well as it would not be possible to achieve the success of democracy. In a democratic system, the Panchayati Raj system is the system through which rural development can be possible. Also, any government can come in contact with common people and take steps for their welfare.

Political awareness means information about the political landscape. Political awareness has a deep connection with participative orientation and political efficiency. In this way, political consciousness is termed as political socialization. Socialization is a process of development through which a person acquires knowledge, dexterity, beliefs, values, attitudes and it enables him to function as an influential member of society.

Political socialization is actually a limitation of the process of socialization in the field of politics and political behavior. It is the process of learning through which a person interchanges the orders and values of the political system.

Dawson and Privet consider it to be the process by which a citizen matures politically. The level of political awareness is a sign of far-reaching consequences in successful running of democracy. If the information about the political processes of the delegates is correct, then their participation in political issues and government work will be meaningful. This will make political decisions easier.

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-2* October- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

मुख्य शब्द : संचेतना – भागीदारी चक्रानुसार क्रमशः।
Consciousness-Participation
Respectively according to the cycle.

प्रस्तावना

लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था में पंचायती राज ही वह माध्यम है जो सरकार को सामान्य–जन के द्वार तक लाता है। लोकतंत्र के उन्नयन में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की विशेष भूमिका रही है। पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय जन सामान्य को शासन कार्य में भागीदार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसी भागीदारी की प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को प्रत्यक्षतः शासन–प्रशासन का प्रशिक्षण स्वतः ही प्राप्त हो जाता है।

राजनीतिक संचेतना का सहभागी अभिविन्यास एवं राजनीतिक दक्षता से गहरा सम्बन्ध होता है। इस प्रकार राजनीतिक संचेतना को राजनीतिक सामाजीकरण की संज्ञा दी जाती है। सामाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति ज्ञान, निपुणता, विश्वासों, मूल्यों, मनोवृत्तियों को प्राप्त करता है तथा यह उसे समाज के एक प्रभावशाली सदस्य के रूप में कार्य करने के योग्य बनाती है।

राजनीतिक सामाजीकरण वास्तव में राजनीति एवं राजनीतिक व्यवहार के क्षेत्र में सामाजीकरण की प्रक्रिया का परिसीमन है। यह सीख की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था के आदेशों एवं मूल्यों का अन्तरीकरण करता है। बर्तमान में शक्ति एवं सत्ता के नवीन आधार स्थापित हो गए हैं जो जाति और वर्ण पर आधारित है। पूर्व में पंचायती राज संस्थाओं में उच्च जाति के सदस्यों विशेषकर पुरूष वर्ग एवं जमीदारों का एकाधिकार था किन्तु अब ऐसा नहीं है। इन संस्थाओं में आरक्षण व्यवस्था के कारण दलित वर्ग के साथ–साथ महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध हुए हैं।

अध्ययन का उददेश्य

प्रस्तुत शोध आलेख का उद्देश्य निर्वाचित महिलाओं की राजनीतिक संचेतना का विश्लेषण करना है। प्रस्तुत शोध आलेख के माध्यम से बुन्देलखण्ड के पिछड़े जनपद हमीरपुर की निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की राजनैतिक सक्रियता के मार्ग में आने वाले अवरोधों का अध्ययन एवं उनका तार्किक विश्लेषण करना है।

अध्ययन क्षेत्र

उत्तर प्रदेश भारत का एक विशाल राज्य है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 294411 वर्ग कि.मी. है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 8.9 प्रतिशत है। क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं आन्ध्र प्रदेश के पश्चात् पांचवां स्थान है किन्तु भारत की जनसंख्या में इसका सर्वाधिक 16.49 प्रतिशत अंशदान होने के फलस्वरूप जनसंख्या की दृष्टि से देश में इस प्रदेश का प्रथम स्थान है। राज्य की न्यूनाधिक राजनीतिक सीमाएं, प्राकृतिक सीमाओं का अनुकरण करती है। प्रदेश का बड़ा भू–भाग गंगा के मैदान के अन्तर्गत आता है। समुद्री सतह से उसकी ऊँचाई 300 मीटर से अधिक नहीं है।

प्रदेश के दक्षिण में पठारी भू–भाग की उत्तरी सीमा यमुना और गंगा नदी द्वारा निर्धारित है। इसके अन्तर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा जनपद आते हैं। गंगा के दक्षिण में पड़ने वाला मिर्जापुर जनपद का भाग तथा वाराणसी जनपद की चकिया तहसील आती है।

तालिका–1

झांसी एवं चित्रकूटधाम मण्डल : जनसंख्यात्मक परिप्रेक्ष्य

क्रं 0	जनपद	क्षेत्रफल वर्ग किमी.	कुल जनसंख्या	पुरूष	महिला
1	हमीरपुर	4282	1104021	593576	510445
2	महोबा	2884	876055	465937	410118
3	बांदा	4460	1799541	966123	833418
4	चित्रकूट	3164	990626	527101	463525
5	जालौन	4565	1670718	895804	774914
6	झांसी	5024	2000755	1061310	939445
7	ललितपुर	5039	1218002	638382	578810

स्रोत जनगणना – 2011

बुन्देलखण्ड भू–भाग के अन्तर्गत आने वाले जनपदों के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या (2011) को तालिका में दर्शाया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झांसी सर्वाधिक (5024 वर्ग किमी.) क्षेत्रफल वाला जनपद है। सबसे कम क्षेत्रफल जनपद महोबा (2884 वर्ग किमी.) का है। जनसंख्या की दृष्टि से झांसी जनपद की जनसंख्या (2000755) सर्वाधिक है तथा सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद महोबा (876055) की है। इस जनपद का सृजन हमीरपुर जनपद को विभक्त करके किया गया है।

राजनीतिक सक्रियता

राजनीति में आने वाले व्यक्ति इसे अपना स्थायी व्यवसाय बनाने का प्रयास करते हैं। राजनीति में इनका मूल्यांकन अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं में अपनी पकड़ बनाकर पुनरावृत्ति की इच्छा रखते हैं। मैटीडोमेन ने अपने अध्ययन में उल्लेख किया है कि नेतृत्व की आवश्यकता विशेषता इसकी असुरक्षा है। व्यवस्थापिका के लिए सदस्य चुनकर आते हैं लेकिन इसकी कोई गारण्टी नहीं है कि वे कब तक सदन के सदस्य रहेगें।

अध्ययन में महिला प्रधानों से यह जानने का प्रयास किया कि उनके परिवार को कोई सदस्य क्या पूर्व में राजनीति में सक्रिय रहा है?

तालिका–2

राजनीति में सक्रियता

क्र.	श्राजनीतिक सक्रियता	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	35	17.5
2	नहीं	165	82.5
	योग–	200	100.0

अध्ययन क्षेत्र की उत्तरदात्रियों के 17.5 प्रतिशत परिवारों के सदस्य राजनीति में सक्रिय रहे हैं। 85.5 प्रतिशत जब कि 85.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के परिवार को कोई भी सदस्य राजनीति में सक्रिय नहीं रहा है। तालिका से स्पष्ट होता है कि महिला प्रधानों के परिवारों की सक्रियता राजनीति में पहले नहीं रही है।

तालिका–3
पूर्व में प्रतिनिधित्व

क्र.	प्रतिनिधित्व	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	17	8.5
2	नहीं	183	91.5
	योग –	200	100.0

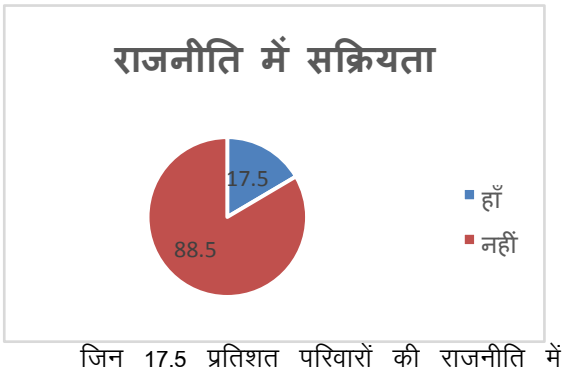

जिन 17.5 प्रतिशत परिवारों की राजनीति में सक्रियता रही हैं उनमें मात्र 8.5 प्रतिशत परिवार के लोग ही पूर्व में पंचायतों का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। जब कि 91.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के परिवार से कोई भी व्यक्ति पूर्व में पंचायत का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं किए रहा है। इन परिवारों से प्रथम बार ही किसी सदस्य को पंचायत का प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

पंचायत चुनाव

पंचायत राज व्यवस्था में आरक्षण की अपनी नियमावली के परिप्रेक्ष्य में आरक्षण का निर्धारण किया जाता है । यह चक्रानुक्रम में होता है। आरक्षण का निर्धारण प्रत्येक पंचवर्षीय चुनाव के पूर्व किया जाता है।

तालिका–4
चुनाव के प्रमुख मुददे

क्र.	प्रमुख मुद्दे	आवृत्ति	प्रतिशत
1	ग्राम विकास	95	47.5
2	सामाजिक सुधार	36	18.0
3	स्थानीय समस्याओं का निवारण	111	55.5
4	सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन	98	49.0
5	महिला एवं बाल विकास को बढ़ावा	45	22.5
6	कोई मुददा नहीं	25	12.5

उत्तरदात्रियों के चुनाव के प्रमुख मुददों को तालिका में दर्शाया गया है। 55.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने स्थानीय समस्याओं के निराकरण करने को, 49.0 प्रतिशत ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को, 47.5 प्रतिशत ने ग्रामीण विकास, 22.5 प्रतिशत ने महिला एवं बाल विकास, 18.0 प्रतिशत ने सामाजिक सुधार को चुनाव के प्रमुख मुददे बनाए। इसके विपरीत 12.5 प्रतिशत ऐसी उम्मीदवार थी जिन्होंने अपने चुनाव में किसी भी कार्य को चुनावी मुददा नहीं बनाया। मुख्यतः चुनाव स्थानीय समस्याओं के निराकरण, ग्रामीण विकास, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लड़े गए।

तालिका–5
उम्मीदवारों की संख्या

क्र.	उम्मीदवारों की संख्या	आवृत्ति	प्रतिशत
1	निर्विरोध	06	3.0
2	एक	11	5.5
3	दो	21	10.5
4	तीन	55	27.5
5	चार या इससे अधिक	107	53.5
	योग –	200	100.0

महिला प्रत्याशियों (विजयी) के विरूद्ध चुनाव में खड़ी हुई उम्मीदवारों की संख्या

तालिका में दर्शायी गयी है। क्षेत्र की 3.0 प्रतिशत महिलाएं निर्विरोध हुई उनके विरूद्ध चुनाव में कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ा, ऐसे प्रत्याशियों के साथ चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं का समर्थन था जिससे उन्हें निर्विरोध निर्वाचित होने का गौरव प्राप्त हुआ। 53.5 प्रतिशत उम्मीदवारों के विरूद्ध 4 या इससे अधिक प्रत्याशी चुनाव लड़े, यह प्रतिशत सर्वाधिक था। 27.5 प्रतिशत उम्मीदवारों के विरूद्ध तीन तक प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। एक या दो विरोधी प्रत्याशियों के विरूद्ध चुनाव लड़ने वालों का प्रतिशत क्रमशः 5.5 तथा 10.5 था। ऐसी उम्मीद है कि पंचायत चुनाव के प्रतिशत बढ़ती लालसा में प्रत्याशियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो तथा निर्विरोध चुनाव जीतना एक दिवास्वप्न होगा।

तालिका–6
मत मिलने या विजयी होने का आधार

क्र.	मत मिलने व विजयी होने का आधार	आवृत्ति	प्रतिशत
1	व्यक्तिगत पहचान/ परिवार का प्रभाव	99	49.5
2	दलीय समर्थन	34	17.0
3	मुददों के आधार पर	49	24.5
4	अच्छा जनसम्पर्क	12	6.0
5	निर्विरोध	06	3.0
	योग –	200	100.0

मत मिलने के आधारों को तालिका में स्पष्ट किया गया है। 49.5 प्रतिशत विजयी प्रत्याशियों को उनकी व्यक्तिगत पहचान अथवा परिवार के प्रभाव के आधार पर मत मिले। यह प्रतिशत सर्वाधिक है। 6.0 प्रतिशत विजयी महिला प्रत्याशियों को अच्छे जनसम्पर्क किए जाने के कारण मत प्राप्त हुए। दलीय समर्थन तथा मुददों के आधार पर मत मिलने वालों का प्रतिशत क्रमशः 17.0 एवं 24.5 है। दलीय आधार पर मत मिलने का कारण प्रदेश में

जिस दल की सरकार बनी उनके समर्थित प्रत्याशियों का मत प्राप्त हुए और वे विजयी हुई। इससे यह संकेत जाता है कि पंचायत स्तर पर भी दलीय प्रभाव परिलक्षित होने लगा है। व्यक्तिगत पहचान पर मत मिलने का आधार राजस्थान के अलवर जनपद में हुए चुनाव से सम्बन्धित अध्ययन से मिलता है। मुददो के आधार पर आधार मत मिलने के संकेत स्पष्ट करते हैं कि ग्राम स्तर पर स्थानीय मुददों के प्रति जन सामान्य में जागरूकता उत्पन्न हो रही है जो ग्रामीण विकास की दृष्टि से सकारात्मक पक्ष को उजागर करती है।

पंचायती राज व्यवस्था एवं आरक्षण

73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायतीराज अधिनियम की धाराओं में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य में पंचायती राज के सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण किया जाएगा। सभी वर्गो की महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की जाएगी। आरक्षण के पीछे मन्तवा सभी वर्गो की महिलाओं को नेतृत्व के सामान अवसर प्रदान करना है जिससे देश की आधी आबादी को अपने वर्ग तथा अपनी महत्वांकाक्षाओं को पूरा करने का अवसर प्राप्त हो सके। आरक्षण के आधारों पर चुनाव लड़ने के पश्चात विजयी महिला प्रधानों से आरक्षण के सम्बन्ध में जानकारी होने की स्थिति का जानने का प्रयास किया गया।

तलिका–7
आरक्षण सम्बन्धी ज्ञान की स्थिति

क्र.	ज्ञान की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	76	38.0
2	नहीं	124	62.0
	योग –	200	100.0

महिला प्रधानों से आरक्षण सम्बन्धी ज्ञान को जानने का प्रयास किया गया। क्षेत्र की 62.0 प्रतिशत उत्तरदात्रियों को आरक्षण क्या होता है इस सम्बन्ध में कोई जानकारी देने से मना किया। यह स्थिति शैक्षणिक पिछड़ेपन या अशिक्षित होने के कारण प्रतीत हुई। इससे शोध की परिकल्पना प्रमाणित होती है। 38.0 प्रतिशत महिलाओं ने आरक्षण के सम्बन्ध में जानकारी दी। इन उत्तरदात्रियों की शैक्षणिक स्तर कमोवेश ठीक था तथा परिवार में राजनीतिक चर्चाएं यदा–कदा होती रहती है जिससे उन्हें कुछ–कुछ जानकारी प्राप्त होती रहती है। विजयी महिला प्रत्याशियों से उनकी सीट के आरक्षण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास अध्ययन में किया गया कि जिस सीट से वह विजयी हुई है उनकी सीट का स्वरूप क्या था ?

तालिका–8
स्थान (सीट) के आरक्षण की स्थिति

क्र.	आरक्षण की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	आरक्षित	120	60.0
2	अनारक्षित	39	19.5
3	पता नहीं	41	20.5
	योग–	200	100.0

उत्तरदात्रियों के सीट के आरक्षण सम्बन्धी जानकारी को तालिका में दर्शाया गया है। 60.0 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने स्पष्ट किया कि उन्होंने आरक्षित सीट से चुनाव लडकर विजय हासिल की है। 19.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों को यह मालूम ही नहीं था कि जिस सीट पर वे पंचायत प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हुई है उनकी सीट का स्वरूप क्या था। तथा इस ओर संकेत करते है कि महिलाओं में अभी भी राजनीतिक संचेतना का अभाव है जिस संस्था का वे प्रतिनिधित्व करती है उसके स्वरूप में भी जानकारी का अभाव है।

नेतृत्व एवं दलीय सम्बद्धता

राजनीतिक दलों द्वारा प्रजातांत्रिक व्यवस्था का संचालन होता है तथा राजनीतिक दल ही शासन पर नियंत्रण रखते हैं। दल की अनुसूचित नीतियों के विरूद्ध जनमत तैयार करना विपक्षी दलों का कार्य होता है। यह शासन दल पर की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। दलीय संगठन के बिना न तो सिद्धान्त की कोई एकीकृत अभिव्यक्ति हो सकती है न नीति का कोई व्यवस्थित उद्विकास हो सकता है। निःसन्देह कोई ऐसी मान्यता प्राप्त संस्थाएं हो सकती हैं जिनके द्वारा कोई राजनीतिक दल शक्ति प्राप्त करने अथवा शक्ति को बनाए रखने का प्रयास करता है। भारतीय राजनीति में बहुदलीय व्यवस्था है। इनकी अपनी विचारधाराएँ, नीतियां एवं कार्यक्रम होते हैं। इनके प्रति लोगों के जुड़ाव में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सक्रिय राजनीति में दलीय सम्बद्धता अनिवार्य सी प्रतीत होती है। स्थानीय स्तर की राजनीति में उच्च स्तर पर कार्यो को करवाने हेतु दलीय सम्बद्धता नितांत आवश्यक होती है। पंचायत चुनावों में दलों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन आवश्यक होता है जो चुनाव परिणामों को प्रभावित करते हैं।

तालिका–9
चुनाव में दलीय सम्बद्धता की स्थिति

क्र.	दलीय सम्बद्धता की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	काँग्रेस	12	6.0
2	भाजपा	13	6.5
3	बसपा	85	42.5
4	सपा	73	36.5
5	निर्दलीय	11	5.5
6	अन्य	06	3.0
	योग –	200	100.0

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-2* October- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

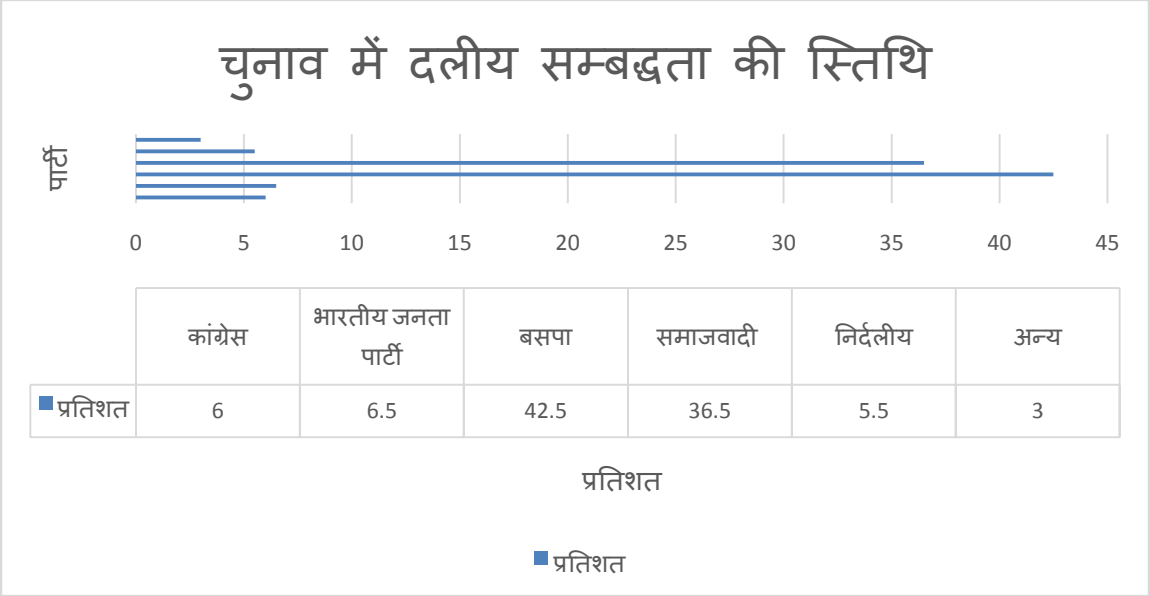

निर्वाचित महिलाओं की राजनीतिक दलों से सम्बद्धता को तालिका में दर्शाया गया है। क्षेत्र की 42.5 प्रतिशत महिलाएं बहुजन समाज पार्टी से सम्बद्ध है। यह प्रतिशत सर्वाधिक है। तथ्यों से स्पष्ट होता है प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एवं समाजवादी पार्टी का प्रभाव काँग्रेस एवं भाजपा की तुलना में अधिक है। कांग्रेस एवं भाजपा से सम्बद्ध रहने वालों का प्रतिशत क्रमशः 6.0 एवं 6.5 है। समाजवादी पार्टी से सम्बद्ध होने वाली महिला प्रधानों का प्रतिशत 36.5 है। 5.5 प्रतिशत महिलाएं किसी भी दल से सम्बद्ध नहीं है। 3.0 प्रतिशत महिलाएं किसी भी दल के प्रति आस्था व निष्ठा को अस्वीकार करती हैं।

बसपा एवं सपा में सम्बद्धता का प्रतिशत अधिक होने का कारण यह है कि दोनो ही दल सत्ता में प्रमुख रूप से काबिज रहते हैं। स्थानीय चुनावों में तात्कालिक प्रभाव से काबिज रहते हैं। स्थानीय चुनावों में तात्कालिक प्रभाव (सत्ता) से लोग अधिक प्रभावित होते हैं। चूंकि कांग्रेस एवं भाजपा विगत कई वर्षो से प्रदेश की सत्ता से दूर रही है।

राजनीतिक चर्चाओं में भागीदारी

लिपमैन की मान्यता है कि राजनीतिक विचार अधिकाशंतः उस संरचना द्वारा निर्मित होते हैं जो व्यक्ति अपने इर्द–गिर्द के वातावरण से प्राप्त करता है। राजनीतिक घटनाओं में साझेदारी, उनके सम्बन्ध में चर्चा या निजी अनुभव ऐसे ही स्रोत है। स्वस्थ जनमत के निर्माण में राजनीतिक चर्चाओं का अपना स्थान है। ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर चुनावों के दौरान दुकानों, चाय–पान की गुमटी चौपालों एवं अन्य प्रमुख स्थानों पर होने वाली चर्चाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

वर्तमान में संचार साधनों में क्रान्ति के कारण देश–विदेश की छोटी सी घटना की जानकारी तुरन्त सम्पूर्ण विश्व में फैल जाती है। नेतृत्व की सजगता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है कि वे राजनीतिक घटनाओं एवं चर्चाओं में कितने सहभागी बनते हैं। नेतृत्व प्राप्त करने के पश्चात महिलाएं अपने आपको यदि किचेन तक सीमित रखेगी तो प्रशासनिक दक्षता पैदा नहीं हो सकती।

जो उत्तरदात्री राजनीतिक चर्चाओं में भागीदारी नहीं करती है उनकी मान्यता है कि गांव के पुरूषों के मध्य बातचीत करना हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि पर्दा प्रथा के चलते हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारे परिवार के पुरूष वर्ग के लोग ही ऐसी चर्चाओं में भागीदारी करते हैं। अधिकांश उत्तरदात्रियों का कहना था कि क्या बातें करें? हमें कुछ पता ही नहीं है। साक्षात्कार के दौरान ऐसा अनुभव हुआ कि पर्दा प्रथा और शैक्षणिक पिछड़ापन राजनीतिक चर्चाओं में भाग न लेने का एक अहम कारण है?

निष्कर्ष

तथ्यों के गहनता से विश्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि ग्रामीण महिला नेतृत्व अभी संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। आने वाले समय में वह अधिक सजग एवं प्रभावी नेतृत्व देने में सक्षम होगा ऐसी समाज की अपेक्षाएं हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *स्टेसी, बी. पोलिटिकल सोशिलाइजेशन इन वेस्टर्न सोसायटी (1978) न्यू देहली पृ0सं0 2*
2. *सिंह, रवि प्रताप, अनुसूचित जाति के विधान मण्डलीय अभिजन (1989) दिल्ली पृ0सं0 85*
3. *डासन, आर.ई., प्रिविट,के., पोलिटिकल सोशिलाइजेशन (1969), वोस्टर्न पृ0सं0 17*
4. *सिंह, जे.एन., लेजिसलेटिव इलिट इन यू.पी., (1983), वाराणसी, पृ0सं0 91 उत्तर प्रदेश वार्षिकी,2013 लखनऊ, पृ0सं0 01*
5. *पूर्वोक्त, पृ0सं0 02*
6. *पूर्वोक्त, पृ0सं0 04*
7. *भारत की जनगणना 2011*
8. *भारत की जनगणना 2011*
9. *पूर्वोक्त*
10. *पूर्वोक्त*

11. *पाण्डेय, डा0 अयोध्या प्रसाद, चन्देलकालीन बुन्देलखण्ड का इतिहास (1968) प्रयाग, पृ0सं0 5*
12. *स्कन्द पुराण, अध्याय 30*
13. *पाण्डेय डा0 अयोध्या प्रसाद, पूर्वोक्त, पृ0सं0 6*
14. *त्रिवेदी, डी.एस. बुन्देलखण्ड का पुरातत्व (1984) झांसी, पृ0सं0 1*
15. *पाण्डेय डॉ0 अयोध्या प्रसाद, पूर्वोक्त, पृ0सं0 6*
16. *अग्निहोत्री, डा0 ए.एन., हमीरपुर (2000), पृ0सं0 21–22*
17. *सिवर्ग जी एण्ड नेट, आर.ए., मैथलॉजी फार रिसर्च (1968) – न्यूयार्क, पृ0सं0 169–77*
18. *सिसोदिया, वाई.एस., पंचायत राज का क्रियान्वयन एवं अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व (2000) जयपुर, पृ0सं0 173*
19. *मल, पूरण, पंचायती राज एवं दलित नेतृत्व (2007) जयपुर पृ0सं0 134*
20. *रिग्स, एफ.डब्लू., कम्प्रेटिव पालिटिक्स एण्ड द स्टडी ऑफ द पालिटिकल पार्टीज : ए स्ट्रक्चर एप्रोच (1968) वोस्टन, पृ0सं0 374*
21. *चोबे हरेन्द्र .निर्वाचित महिला ग्राम प्रधानों का एक अध्ययन .अप्रकाशित शोध प्रबन्ध (2014)*